स्मरणीय है कि बक्सर के पास यदि गंगा की धारा बदल गई, तो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा का पुल भी बेकार हो जायेगा ।

इसी प्रकार पटना जिला स्थित मनेर प्रखण्ड के जीवरासन टोला का आधा से अधिक हिस्सा विलीन हो गया, लेकिन संसद् में इस पर चर्चा के बाद भी वहा के लोगों को बसने की जमीन नही दी गई है । ग्रामीण इधर-उधर मारे मारे फिर रहे हैं ।

अत: सरकार से आग्रह है कि वह भोजपुर जिला और रेलवे लाइन को बचाने के लिए तुरन्त उचित कार्यवाही करे तथा पटना जिला स्थित जीवरासन टोला के कटाव पीडितो के लिए जमीन की शीघ्र व्यवस्था करे ।

(iv) DEMAND FOR ADEQUATE SUPPLY OF GROUNDNUT SEED TO GROUNDNUT RESEARCH INSTITUTE AT SITAPUR, UTTAR PRADESH.

श्री राम लाल राही : (मिसरिख) उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर भारत के उ० प्र० में जनपद सीतापुर तथा उसके सीमावर्ती जनपदो जैसे हरदोई, शाहजहापुर, लखीमपुर आदि उत्तम मूगफली उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सीतापुर जनपद व्यावसायिक दृष्टि से तिलहन के क्षेत्र में उत्तर भारत की प्रमुख मण्डी कई दशको में बन गया था । यही नही, केवल जनपद सीतापुर मे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रो मे करीब डेढ सौ छोटे बडे उद्योग मूगफली तिलहन पर आधारित है ।

इधर करीब 4–5 वर्षों से मूगफली की क्वालिटी और क्वांटिटी मे निरन्तर गिरावट आने के कारण इन जनपदो का मूगफली उत्पादन क्षेत्र भुखमरी का शिकार होता जा रहा है । यही नही, मूगफली पर आधारित उद्योग चौपट हो गया है । लगभग 90 प्रतिशत कारखाने बन्द व वीरान पड़े है । किसानो के सामने बीज का निरन्तर सकट बना हुआ है । 15 से 20 रुपया किलो तक नकद बीज तलाश करने पर भी बाजारों मे नहीं मिला । केवल जनपद सीतापुर के 40 हजार एकड़ क्षेत्र के लिए केवल 120 क्विटल बीज की व्यवस्था सरकार ने की, वह भी नकद दाम देकर । परिणाम यह हुआ कि नाममात्र को भी बीज नहीं उठा । परिस्थिति यह है कि जनपद सीतापुर सहित अनेक पड़ोसी जिलो मे हजारों एकड़ मूगफली उत्पादक क्षेत्र वीरान व बंजर पड़ा है ।

सरकार की उपेक्षापूर्ण किसान विरोधी नीति के कारण ही इस मूगफली उत्पादक क्षेत्र के कपसा कला गाव मे गत वर्ष 7 लोगों की भूख से मौत हो गई थी । भविष्य मे भी भुखमरी से इन क्षेत्रो मे लोगो के मरने की कुसम्भावनाये पैदा हो गई है ।

सरकार तिलहन उत्पादन के अभाव मे प्रति वर्ष करोड़ो की मुद्रा खाद्य तेलो के आयात मे लगा रही है । परन्तु यदि मूगफली (तिलहन) उत्पादन की तरफ सरकार का विशेष ध्यान जाये और मूगफली उत्पादन क्षेत्र, खासकर उत्तर भारत की प्रमुख मण्डी सीतापुर मे शोध सस्थान बनाया जाये, बीज वितरण की सही व्यवस्था की जाये तो खाद्य तेलो मे आत्म-निर्भर होने के साथ ही विदेशी मुद्रा के अपव्यय पर भी नियन्त्रण हो सकता है ।

मै इस लोक महत्त्व के प्रश्न को उठाते हुए विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हू कि सरकार इस सबध मे व्यवस्था करे और एक वक्तव्य दे ।

(v) DISCOVERY AND COLLECTION OF GOLD PARTICLES IN RAIGARH DISTRICT OF MADHYA PRADESH FOR SOME BUSINESSMEN.

SHRI B R. NAHATA (Mandsaur): Mr. Deputy Speaker, Sir, under Rule

[Shri B. R. Nahata]

377 I invite the attention of this Hon. House to the fact that 15,000 people are engaged in collecting gold from Tapkara and Farsa Bahar two Development Blocks in Madhya Pradesh in Raigarh District, where gold particles even of 10 gms. weight are found. This gold is collected for some businessmen who purchase or get it collected from labourers paying them 7 to 8 rupees per day as labour charges and the daily collection of gold is about 1.25 lacs of rupees. The attention of the Government is drawn to this aspect for an immediate action for a problem of public importance.

(vi) SHORTAGE OF CEMENT AND SUGAR IN UTTAR PRADESH.

SHRI ZAINUL BASHER (Gazipur): Mr. Deputy Speaker, Sir, due to non-supply of cement and sugar, Uttar Pradesh is facing acute shortage. There was very little sugar availability to consumers during the Id Festival. The Hindu Festivals are also due within 2-3 months, and there will certainly be rise in the demand of sugar. If the Government will not come to the rescue, the State Government of Uttar Pradesh will be handicapped and the consumers will suffer.

The building activities in Uttar Pradesh have come to standstill due to non-availability of cement during rainy season this year. Cement is not available even for the purpose of repairs. The Central Government have affected 50 per cent cut in the allocation of cement quota in Uttar Pradesh. The cement available to the State is insufficient even for Government constructions. The developmental activities too have come to a static state for want of cement.

I, therefore, urge upon the Government to supply cement and sugar to the State of Uttar Pradesh as per their demands as early as possible.

(vii) DEMAND OF NATIONALISATION OF J. K. MANUFACTURERS (KAILASH MILLS), KANPUR.

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स (कैलास मिल) कानपुर की समस्या की ओर मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कपड़े का यह मिल गैर-कानूनी तौर पर ता० 10 अक्तूबर, 1976 से बन्द पड़ा है। इस मिल के मजदूरों को पिछले 5 वर्षों में अत्यन्त दयनीय जीवन बिताने के लिये मजबूर किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठा के इस कारखाने के मजदूरों ने रिक्शा चला कर और दूसरे अनिपुण कार्य कर किसी तरह अपने आप को जीवित रखा। परन्तु इसी बीच अनेक मजदूरों ने कठिनाइयों से तंग आ कर आत्महत्या कर ली और कुछ कानपुर छोड़ कर चले गये। इस मिल को खुलवाने या राष्ट्रीयकरण के लिये अनेक ज्ञापन दिये गये है। पिछले वर्ष लोक सभा में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी संतुस्ति भेज चुकी है और राष्ट्रीयकरण के विषय पर शीघ्र ही निर्णय हो जायगा। मई, 1981 में मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल को माननीय वाणिज्य मंत्री ने मेरी उपस्थिति में आश्वासन दिया था कि किसी विलम्ब के बिना मिल खोल दिया जायेगा। अभी इसी महीने 2 अगस्त को कानपुर में मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला और उनके नेता ने कहा कि चूंकि मिल नहीं खोली जा रही है इसलिये मजदूरों के एक नेता श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी अपने प्राणों की बलि ता० 10 अगस्त को देंगे। मेरे समझाने पर रजामन्दी दिखाने के बावजूद श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी ने 11 अगस्त को बिजली का तार पकड़ कर अपनी जान दे दी।

अब यह समस्या गम्भीरता की सीमा पार कर चुकी है। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि अब स्थिति के और बिगड़ने के पहले इस मिल का राष्ट्रीयकरण कर मजदूरों को बचाया जाय।